प्रदेश बनेगा तकनीकी वैश्विक क्षमता का केंद्र

उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता नीति केंद्र (यूपी जीसीसीसी) के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इस मद में एक लाख रुपये की प्रतीकात्मक व्यवस्था की गई है। यूपी जीसीसी नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और राज्य को डिजिटल सेवाओं, अनुसंधान व उच्च मूल्य संचालन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए इन लाभों को भुनाना है।

यूपी को अब वैश्विक क्षमता केंद्र का सुपर हब बनाने की तैयारी है। नीति के तहत निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 100 फीसदी राहत देने के साथ ही कई सहूलियतें दी जाएंगी। एक हजार जीसीसी स्थापित करने के लक्ष्य के साथ ही लगभग पांच लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीसीसी ऐसे सुविधायुक्त केंद्र होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा, डाटा विश्लेषक, रोबोटिक्स और क्लाउड-क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि पर कंपनी को तकनीकी सेवा उपलब्ध कराते हैं।

यूपी जीसीसी के लिए पहली बार खोला खजाना

साइबर सिक्योरिटी के साथ ऑनलाइन होंगे सभी विभाग

साइबर सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान

प्रदेश सरकार के विभागों में डाटा मैनेजमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा। इसके लिए बजट 1.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के लिए 2.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मैनुअल काम करने वाले विभागों को ऑनलाइन बनाने के लिए तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की गई है। यूपी डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट्स एंड इम्प्लायमेंट प्रमोशन पालिसी के तहत निवेशकों को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।